



04 - शादियों पर दिखावा  
बंद हो



05 - 25 बांधों की मौत फिर  
करने की बात है...

A Daily News Magazine

मोपाल

सोमवार, 29 जुलाई, 2024



मोपाल एवं इंडैट से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 21 अंक 322 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रु. 2 (डाक पंजीयन संख्या: म.प्र./मोपाल/4-391/2018-20)



06 - इंडिगिंग बहसात से बड़ी  
किसानों की चिंता



07 - नर्मदापुर में बह दूरी है  
रेज शिव मंत्री की बायार

# मोपाल

# मोपाल

पहली बात



उमेश त्रिवेदी  
संपादक

9893032101

## नीति आयोग : विपक्ष के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी का औजार?

**बं**गल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के बैठकटॉन ने प्रधानमंत्री ने रेज मोदी का प्रिय कठिये में है। ममता बैनर्जी ने शनिवार 27 जुलाई को आयोजित नीति आयोग की सालाना बैठक का बैठकटॉन करते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें अपने राज्य का पक्ष खरेने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। उनके भाषण के दृष्ट्यान जानवरकर उनका माइक बंद करना अपाराजक है। नीति आयोग का दुर्घटयोग विपक्षी राज्य-सरकारों के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी के रूप में किया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री की कठपुतली है, जिसे कोई अधिकार नहीं है। इसे बर्खास्त करके योजना आयोग जैसी ताकतवर सस्ता को फिर से खड़ा किया जाना चाहिए।

योजना आयोग को फिर से खड़ा करने की मांग का राजनीतिक अकार बढ़ने लगा है।

प्रधानमंत्री ने रेज मोदी 2015 को देश में सक्रिय मैसेंट साल पूर्ण योजना आयोग को भाँग करके नीति आयोग का गठन किया था। इसे सरकार का धिक्कैटैक माना जाता है। गैरतलब है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जाहाङ्गील नेहरू ने 1950 में केन्द्र सरकार द्वारा गठन किया गया था। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सहित केन्द्र सरकार के प्रवक्ताओं ने ममता बैनर्जी के आरोपों को गठनीतिक दुश्ग्राह और निषादर निरूपित किया है। बहाहाल ममता बैनर्जी के आरोपों की पूर्णता जरिया उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह सवाल मौजूद है कि विपक्ष

नीति आयोग और योजना आयोग के बीच तुनियादी फरक यह है कि नीति आयोग एक सरकारी निकाय है, जिसके पास नीतियों और निधियों को लागू करने से संबंधित कोई तकत नहीं है, जबकि पूर्ववर्ती योजना

आयोग के पास नीतियों को लागू करने और राज्यों को निधि आवंटित करने का मर्तबा अधिकार है। योजना आयोग देश की सभी विकास योजनाओं को बनाने के लिए जिम्मेदार था। राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदृश्य होते थे। गैरपर मसला यह है कि नीति आयोग का राजनीतिकरण नीतिगत अवधारणाओं में सबसे बड़ा प्रतिरोधक बनकर उभर रहा है।

गैरतलब है कि इंडिया-गठबंधन शासित राज्यों द्वारा आयोग की बैठक के बैठकटॉन के आव्वान के बावजूद ममता बैनर्जी ने शनिवार, 27 जुलाई को आयोजित आयोग की बैठक में शरीक होने का फैसला किया था। मोदी-सरकार द्वारा बैठकटॉन में विपक्षी राज्य-सरकारों के साथ सोनेते व्यवहार के आरोपों की बजह से इंडिया-गठबंधन ने नीति आयोग की बैठक के बाबत का आव्वान को बैठक के बाबत का आव्वान हो चुका है। बैठक में 10 राज्य और केन्द्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शरीक नहीं हुए थे।

इंडिया-गठबंधन का कहना है कि आयोग की बैठक में ममता बैनर्जी के साथ यह सल्लूक इस केन्द्र सरकार के सोनेतेपन की पुष्टि करता है। बैठक को अधिरा छोड़ कर बाहर निकलने के बाद ममता बैनर्जी के आरोपों ने मोदी-सरकार और विपक्ष के बीच दरार को गहरा कर दिया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सहित केन्द्र सरकार के प्रवक्ताओं ने ममता बैनर्जी के आरोपों को गठनीतिक दुश्ग्राह और निषादर निरूपित किया है। बहाहाल ममता बैनर्जी के आरोपों की पूर्णता जरिया उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह सवाल मौजूद है कि विपक्ष

के बहिष्कार के आव्वान के बावजूद आयोग की बैठक में शरीक होने वाली ममता बैनर्जी का अकरण ही अतह अंतरिक समय मांग सकती थी। हर बैठक के बहिष्कार वयों को कहा चाहिए?

ममता बैनर्जी का मत था कि नीति आयोग प्रधानमंत्री के सम्मुख अपने राज्य की मांगों को रखने का सबसे उपयुक्त और सीधा मंच है। इसीलिए विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा इसका दर्शकनार के बैठक के बावजूद ममता बैनर्जी के शरीक होने पहुंच थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें बोलने का पर्याप्त मौका ही नहीं दिया गया। जबकि, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए ज्यादा समय दिया गया। ममता बैनर्जी का कहना था कि विपक्षी राज्यों की ओर से बोलने वाली वो एकमात्र मुख्यमंत्री थी।

उनका कहना है कि आध्र के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट का समय दिया गया था। असम, गोवा और छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी दस-बारह मिनट तक अपने बात रखी, लेकिन जब मैं बोल रही थी तो मेरा माइक पांच मिनट में ही बंद कर दिया गया। यह सिर्फ बांगल का ही नहीं, बल्कि सभी दलों का अपनान है। केन्द्र-सरकार द्वारा राज्य-सरकारों के साथ पक्षपालपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

ममता बैनर्जी के आरोपों के प्रति उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कहना है कि यह पूरी तरह झूठ है कि ममता बैनर्जी का माइक बंद कर दिया गया। हंगर मूख्यमंत्री को बोलने

के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। अगर वह और बोलना चाहती थीं तो अन्य मुख्यमंत्रियों की अकरण ही अतह अंतरिक समय मांग सकती थीं। हर बैठक के सामने एक झूली थी। बैठक का संचालन राज्यमंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। सभी वकालों के बब्ब पूरा होने पर राजनाथ सिंह टैप करते थे, जिसे सभी वका सुनते थे। सभी मुख्यमंत्रियों के लिए यह इशार किया गया था। उन्हें भी इशार किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें बोलने का पर्याप्त मौका ही नहीं दिया गया।

ममता बैनर्जी के बैठकटॉन ने नीति आयोग के खिलाफ प्रतिक्रियों में आग में थी जैसा काम किया है। केंद्र-सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुख्खा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवत रेड़ी ने फैले ही घोषित कर दिया था कि केन्द्र-सरकार के भेदभावपूर्ण बजट आवंटन के विशेष में वो नीति आयोग की बैठक में शरीक नहीं होगी। तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन, केरल के पिनाराई विजयन और आम आदमी पार्टी के विल्स और पंजाब सरकार भी इसी मूले पर बहिष्कार की बैठक में बोलने की ओर आवंटन नहीं होगी। बैठक का एजेंडा 2017 तक भारत को विकासित राष्ट्र बनाने पर केन्द्रित था। कांग्रेस ने कहा है कि नीति आयोग नॉन-बॉयलोजिकल प्रधानमंत्री के लिए ढोल पीटने वाला एक त्रैत्र के रूप में काम करने वाला सांठन है। इस संघटन में असहमति के लिए कोई जारी नहीं है। यह ठेट अन-प्रैफेशनल बोली है।

## उत्तर प्रदेश में बाढ़, 350 गांव इब्बे

देश के कई राज्यों में तेज बारिश, बाढ़ जैसे हालात



### बहुत भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडू, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश

के 4 और गैट खोलने पड़े। पहले से ही 16 गेट खुले हैं।

इसमें आस-पास के इलाकों में पानी भर गया। उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने चलते चार लोगों की मौत हो गई।

जबकि इन दो राज्यों के निकाय ने उन्हें बोला रखा है कि वे बाहर नहीं हो सकते।

यह अपने गांव में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। यह अपने गांव में एक इंटरव्यू के दौरान इन बारिश का बाहर नहीं हो सकता।

यह अपने गांव में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। यह अपने गांव में एक इंटरव्यू के दौरान इन बारिश का बाहर नहीं हो सकता।

यह अपने गांव में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। यह अपने गांव में एक इंटरव्यू के दौरान इन बारिश का बाहर नहीं हो सकता।

यह अपने गांव में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। यह अपने गांव में एक इंटरव्यू के दौरान इन बारिश का बाहर नहीं हो सकता।

यह अपने गांव में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। यह अपने गांव में एक इंटरव्यू के दौरान इन बारिश का बाहर नहीं हो सकता।













